

प्रेषक.

डी०एस० गर्ब्याल, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक भुनित्रिया

विषय : वित्तीय वर्ष 2015—16 में नगर निगम, देहरादून को सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून द्वारा देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के दृष्टिगत विभिन्न सामग्री क्रय / निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून को निम्न विवरणानुसार कुल ₹235.00 लाख (रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	नशाश रू० लाख में)
1.		कार्य की लागत
2.	100 Underground Dustbin निर्माण 30 डी0पी0 बिन क्रय	100.00
3.		15.00
	DVWM से प्राप्त टाटा ऐस गाड़ियों की खरीद एवं मरम्मत का	50.00
	डी०पी० वाहन क्रय	
	बोबकेट / जे0सी0बी0 क्रय	30.00
		40.00
याग-		235.00

- 2- उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :--
- उक्त धनराशि कुल ₹235.00 लाख (रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- II. 100 Underground Dustbin निर्माण हेतु रू. 100.00 लाख की धनराशि उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही है, उक्त के अतिरिक्त रू. 100.00 लाख की धनराशि एम0डी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं योजना हेतु शेष धनराशि नगर निगम, देहरादून द्वारा वहन की जायेगी।
- ा।. स्वीकृत कार्य/क्रय हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- V. क्रय किए जाने वाले सफाई वाहनों का सम्पूर्ण क्रय विवरण शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

ा. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

II. स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु निर्धारित अविध के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और

किसों भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

ाा. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यजनर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सनिश्चित करें।

IV. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी / तकनीकी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

v. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से

उत्तरदायी होगी।

VI. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमित अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

VII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा

उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

VIII. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

IX. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो

उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

x. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का

विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक के **अनुदान सं0—13** के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०— 437/XXVII(2)/2015, दिनांक 28.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—s./.5.691.3.6.644. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय, (डीoएसo गर्ब्याल) सचिव। संख्या- ४२५(1)/10(2)-शा0वि0-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।

3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4. अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

जिलाधिकारी, देहरादून।

उपाध्यक्ष, एम०डी०डी०ए०, देहरादून।

वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

9. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

- 10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
- 11. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि योजना हेतु रू. 100.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था एम0डी0डी0ए0 के माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

13. गार्ड बुक ।

आज्ञा स्ने,

( डी०एम०एस० राणा ) उप सचिव।